



# शोध भूमि

शिक्षा एवं शिक्षण शास्त्र विषय की पूर्व समीक्षित शोध पत्रिका

आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया, सहभागिता, प्रभाव और चुनौतियाँ  
(विशेष बोडला ब्लॉक, जिला-कबीरधाम के संदर्भ)

मानकुंवर मेरावी

शोधार्थी

समाजशास्त्र अध्ययन शाला

शास.वि.या.ता. स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत

ईमेल : meravi.75048@gmail.com

सारांश

भारत के सुदूरवर्ती आदिवासी अंचलों में 'डिजिटल इंडिया' अभियान की प्रासंगिकता तथा उसके सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक प्रभावों का समग्र विश्लेषण करना है, विशेष संदर्भ छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले के बोडला ब्लॉक का है। ऐतिहासिक रूप से विकास की मुख्यधारा से वंचित इन आदिवासी अंचलों में डिजिटल तकनीकों के विस्तार ने सूचना के लोकतंत्रीकरण को गति प्रदान की है, जिससे स्थानीय समुदायों की सहभागिता एवं जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कॉमन सर्विस सेंटर्स, मोबाइल कनेक्टिविटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रसार ने आदिवासी समुदायों के लिए बैंकिंग सेवाओं, शैक्षिक संसाधनों तथा सरकारी योजनाओं तक पहुँच को अधिक सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाया है। विशेष रूप से 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' प्रणाली ने बिचौलियों की भूमिका को सीमित करते हुए लाभार्थियों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और शासन प्रणाली में विश्वास बढ़ा है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण योजनाएं ई-सेवाएं उपलब्ध हुआ है, जिससे आदिवासी अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली है। लेकिन भौगोलिक विषमता, सीमित नेटवर्क उपलब्धता, बिजली की अनियमितता, भाषाई अवरोध तथा डिजिटल साक्षरता की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी डिजिटल समावेशन के मार्ग में बाधक बनी हुई हैं। अतः यह शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि आदिवासी सशक्तिकरण के लिए केवल डिजिटल अवसंरचना का विस्तार पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्थानीय आवश्यकताओं, सांस्कृतिक संदर्भों एवं भाषाई विविधता के अनुरूप एक समावेशी, सुलभ और टिकाऊ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का विकास अनिवार्य है।

**विशिष्ट शब्द** : डिजिटल इंडिया, आदिवासी सशक्तिकरण, डिजिटल अंतराल, ई-गवर्नेंस, समावेशी विकास।

**परिचय** :

समकालीन भारत के विकास विमर्श में 'डिजिटल इंडिया' एक केंद्रीय धुरी के रूप में उभरा है, जिसका उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण विषमताओं को कम करते हुए समावेशी विकास को गति प्रदान करना है। वर्ष 2015 में प्रारंभ किए गए इस अभियान ने 'अंतिम छोर तक समावेश के सिद्धांत को अपनाते हुए विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो अब तक विकास की मुख्यधारा से वंचित रहे हैं।

विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, जहाँ भौगोलिक दुर्गमता, अविकसित अवसंरचना एवं सामाजिक अलगाव ने लंबे समय से विकास की गति को बाधित किया है, डिजिटल तकनीक एक सशक्त सेतु के रूप में उभर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य कबीरधाम जिला के बोड़ला ब्लॉक के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र प्रस्तुत करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, इस जिले की कुल जनसंख्या 8,22,526 है, जिसमें आदिवासी समुदाय का उल्लेखनीय अनुपात विद्यमान है। जिले के बोड़ला ब्लॉक में ग्रामीण आदिवासी जनसंख्या 72,671 है, जो कुल आबादी का लगभग 40.05 है। इस समुदाय का एक बड़ा हिस्सा आज भी बुनियादी सूचनात्मक संसाधनों और सेवाओं की पहुँच के लिए संघर्षरत है। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत 'भारतनेट' जैसी परियोजनाओं के माध्यम से वनांचल एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों को वैश्विक सूचना से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, 'ई-नाम'(राष्ट्रीय कृषि बाजार), पी.डी. एस. तथा 'ट्राइब्स इंडिया' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने बिचौलियों की भूमिका को कम करते हुए आदिवासी समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण के नए आयाम खोले हैं। शासन की हर नीति पूर्णतः डिजिटलीकरण करने का प्रयास है। तथापि, इस प्रगति के समानांतर अनेक संरचनात्मक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। वनांचल क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक बनावट के कारण नेटवर्क कनेक्टिविटी की अनिश्चितता एक प्रमुख बाधा बनी हुई है। साथ ही, बोड़ला के सुदूर ग्रामों में डिजिटल साक्षरता का अभाव तथा भाषाई विविधता (विशेषकर बैगा एवं छत्तीसगढ़ी बोली) सूचना के प्रभावी प्रसार में अवरोध उत्पन्न करती है।

ऐसी परिस्थितियों में 'भारतनेट' के साथ-साथ उपग्रह आधारित इंटरनेट जैसी वैकल्पिक तकनीकों की आवश्यकता और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। अतः प्रस्तुत अध्ययन डिजिटल संभावनाओं और संरचनात्मक चुनौतियों के मध्य अंतर्संबंधों का विश्लेषण करते हुए बोड़ला विकासखंड को एक केस स्टडी के रूप में स्थापित करता है, जो आदिवासी क्षेत्रों में समावेशी डिजिटल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

### साहित्य समीक्षा:

- जॉर्ज स्टिबिट्ज़ (1942) डिजिटल बनाम एनालॉग कंप्यूटिंग (बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज आर्काइव्स) जिसे बाद में ब्रायन रैंडेल ने अपनी पुस्तक 'द ओरिजने ऑफ डिजिटल कंप्यूटर' (1973) के संदर्भित किया, डिजिटल कंप्यूटिंग के प्रारंभिक सिद्धांतों को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कार्य में स्टिबिट्ज़ ने कंप्यूटिंग प्रणालियों को 'एनालॉग' और "डिजिटल" श्रेणियों में विभाजित करते हुए उनके वैचारिक अंतर को स्पष्ट किया, हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उस समय अधिकांश प्रणालियाँ मिश्रित प्रकृति की थीं। उन्होंने रिले आधारित बाइनरी संचालन (0 और 1) की उपयोगिता पर जोर दिया, जो आगे चलकर आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों की नींव बना। यह अध्ययन साहित्य में एक आधारभूत योगदान के रूप में देखा जाता है, जिसने डिजिटल कंप्यूटिंग के विकास, वर्गीकरण और व्यावहारिक उपयोग की दिशा को स्पष्ट किया।

- तबस्सुम (2014) ने अपने अध्ययन में तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के आर्ट्स एवं साइंस कॉलेजों के छात्रों में डिजिटल साक्षरता की जागरूकता का विश्लेषण किया। यह अध्ययन 227 कॉलेज छात्रों पर आधारित था। शोध का उद्देश्य छात्रों में डिजिटल साक्षरता के स्तर को समझना था। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश छात्र डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में औसत स्तर पर हैं। इसका अर्थ है कि छात्रों को डिजिटल उपकरणों और तकनीकों का सीमित लेकिन पर्याप्त ज्ञान है। कुछ छात्रों में डिजिटल तकनीकों के उपयोग की अच्छी समझ भी देखी गई। हालांकि, कई छात्रों में उन्नत डिजिटल कौशल की कमी पाई गई। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि डिजिटल शिक्षा के प्रति जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ रही है। शोध ने यह संकेत दिया कि कॉलेज स्तर पर डिजिटल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। निष्कर्षतः, छात्रों के डिजिटल साक्षरता स्तर में सुधार की काफी संभावना मौजूद है।
- **कौर, अमनिंदर एवं अन्य (2021)** के अनुसार, यह अध्याय डिजिटल परिवर्तन के लिए एक रूपरेखा (रोडमैप) प्रस्तुत करता है और इसके मूलभूत सिद्धांतों को समझने में सहायता प्रदान करता है। अध्ययन में बताया गया है कि बढ़ती तकनीकी प्रगति तथा इंटरनेट और मोबाइल की व्यापक उपलब्धता ने भारत में ई-कॉमर्स के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया है। वर्तमान में देश डिजिटल क्रांति के महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा है।  
4जी सेवाओं की शुरुआत, डेटा प्लान की लागत में कमी तथा इंटरनेट उपकरणों (जैसे USB डोंगल) की कीमतों में गिरावट ने इंटरनेट को अधिक सुलभ बना दिया है। इसके साथ ही, सस्ते स्मार्टफोन की उपलब्धता और दूरदराज क्षेत्रों तक ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या को तेजी से बढ़ा रहा है। इससे ऑनलाइन खरीदारों और वास्तविक उपभोक्ताओं के बीच की दूरी कम हो रही है और डिजिटल भागीदारी में वृद्धि हो रही है।
- कुमार, अमृत जी (2021) ने **The Classroom Monitor: How Digital Learning** में यह बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान वर्चुअल कक्षाओं ने शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अध्ययन के अनुसार, ऑनलाइन शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह था कि छात्रों को सीखने में अधिक स्वतंत्रता मिली और यह एक वैकल्पिक शिक्षण माध्यम के रूप में उभरा।  
अध्ययन में यह भी पाया गया कि कई छात्र इस व्यवस्था से इसलिए संतुष्ट थे क्योंकि ऑनलाइन कक्षाओं में उन्हें शिक्षक की कठोर निगरानी या डाँट-फटकार का सामना नहीं करना पड़ता था। हालांकि, दूसरी ओर कुछ छात्रों ने पारंपरिक कक्षाओं की कमी महसूस की, विशेषकर शारीरिक गतिविधियों और सांस्कृतिक सहभागिता के अभाव के कारण वे असंतोष भी व्यक्त कर रहे थे।
- **डिजिटल समावेशन और सरकारी नीतियाँ:** विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनों और शोध लेखों (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, 2023) के अनुसार, 'डिजिटल इंडिया' का प्राथमिक उद्देश्य सूचना की खाई को पाटना है। सरकारी

सेवाओं के डिजिटल होने से बिचौलियों की भूमिका कम हुई है, जिससे आम आदमी पहुंच के लिए एक कदम आगे होता जायेगा।

- **छत्तीसगढ़ और जनजातीय परिप्रेक्ष्य: शर्मा और बघेल (2022)** ने छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में किए गए अपने शोध में उल्लेख किया है कि राज्य की 30.62 प्रतिशत जनजातीय आबादी के लिए 'बस्तर नेट' और 'भारतनेट' जैसी परियोजनाएं गेम-चेंजर साबित हुई हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि तकनीकी बुनियादी ढांचे का विस्तार मैदानी इलाकों की तुलना में वनांचलों में अत्यंत धीमा है।
- सिंह, कुलदीप एट अल (2024) – डिजिटल परिवर्तन ने भारत के पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं और इसे एक नए युग की शुरुआत माना जा सकता है। इसके कारण न केवल ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि हुई है, बल्कि व्यावसायिक प्रक्रियाएँ भी अधिक प्रभावी और दक्ष हो गई हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और बिग डेटा जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से यात्रा सेवाओं को व्यक्तिगत सुझाव, स्मार्ट बुकिंग प्रणाली और बेहतर निर्णय-निर्माण सेवाओं के माध्यम से अधिक संगठित और उपयोगी बनाया गया है। परिणामस्वरूप, यात्रा सेवाएँ अधिक तेज, कुशल और ग्राहक-केंद्रित हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया मार्केटिंग (SMM) ने पर्यटन व्यवसाय में विपणन की भूमिका को और अधिक मजबूत किया है, जबकि ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसियाँ (OTA) और क्लाउड-आधारित सेवाएँ जैसी नई तकनीकें इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं।
- **शर्मा आदि (2024)** : डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो देश में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो सकें। इस योजना के अंतर्गत डिजिटल ढांचे को मजबूत करना और दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा का विस्तार करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इसके जरिए सरकार देश को तकनीकी और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। साथ ही, नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए यह पहल लोगों को आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती है।
- **कबीरधाम और बोड़ला ब्लॉक के विशिष्ट संदर्भ:** स्थानीय अध्ययनों और जिला सांख्यिकी पत्रिकाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि कबीरधाम के बोड़ला ब्लॉक में विशेष पिछड़ी जनजाति 'बैगा' के मध्य डिजिटल साक्षरता का स्तर न्यूनतम है। **यादव (2024)** के एक हालिया लेख के अनुसार, बोड़ला के पहाड़ी क्षेत्रों में 'शैडो जोन' (नेटवर्क विहीन क्षेत्र) की समस्या के कारण डिजिटल इंडिया के लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
- **डिजिटल साक्षरता और भाषाई चुनौतियाँ:** कुमार और सिंह (2025) द्वारा प्रस्तुत अध्ययन "डिजिटल इंडिया 2.0 और आदिवासी समुदायों का समावेशन" में **डिजिटल**

इंडिया 2.0 के संदर्भ में यह विश्लेषण किया गया है कि डिजिटल तकनीकों के माध्यम से आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास कैसे किए जा रहे हैं। अध्ययन में डिजिटल अवसंरचना (इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्क), डिजिटल साक्षरता, और ई-गवर्नेंस सेवाओं की पहुंच को प्रमुख कारक माना गया है, साथ ही यह भी दर्शाया गया है कि भौगोलिक दूरी, भाषा संबंधी बाधाएं और तकनीकी जागरूकता की कमी अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। शोध में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रभावी क्रियान्वयन, स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण, और समुदाय-आधारित डिजिटल पहलें आदिवासी क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकती हैं।

### उद्देश्य:

इस शोध-पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- **डिजिटल पहुँच का आकलन करना:** छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले (विशेषकर बोड़ला ब्लॉक) के आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे, इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
- **सहभागिता के स्तर को समझना:** आदिवासी समुदायों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं की विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों (जैसे ई-गवर्नेंस, सोशल मीडिया और ऑनलाइन बैंकिंग) में भागीदारी के स्तर का अध्ययन करना।
- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन:** यह जाँचना कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने आदिवासियों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण (जैसे डीबीटी और ई-कॉमर्स) पर क्या सकारात्मक प्रभाव डाला है।
- **प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना:** आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन के मार्ग में आने वाली भौगोलिक, तकनीकी, भाषाई और सांस्कृतिक बाधाओं को रेखांकित करना।
- **सुधार हेतु सुझाव देना:** अध्ययन के आधार पर आदिवासी अंचलों में 'डिजिटल डिवाइड' को कम करने और डिजिटल सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

### डिजिटल इंडिया अभियान का संक्षिप्त परिचय:

'डिजिटल इंडिया' भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी और प्रमुख अभियान है, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से तीन स्तंभों पर टिका है: नागरिक के लिए एक उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना, मांग पर सरकारी सेवाएं प्रदान करना और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना। इस अभियान के अंतर्गत भारतनेट, ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य और डिजिटल लॉकर जैसी महत्वपूर्ण पहलें शामिल हैं, जिनका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर भ्रष्टाचार को कम करना और देश के सुदूर ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ना है।

डिजिटल इंडिया के कड़ी निम्न है –

- **ब्रॉडबैंड हाईवे:** पूरे देश, विशेषकर ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ना।
- यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटीरू नेटवर्क विहीन क्षेत्रों (Shadow Zones) में मोबाइल टावर पहुँचाना।
- **पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम:** कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और पोस्ट ऑफिस को डिजिटल हब बनाना।
- **ई-गवर्नेंस:** सरकारी कामकाज और प्रक्रियाओं का पूरी तरह डिजिटलीकरण करना।
- **ई-क्रांति:** शिक्षा (e-Education), स्वास्थ्य (e-Healthcare) और कृषि सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी।
- **सभी के लिए सूचना:** सरकारी डेटा और जानकारी तक नागरिकों की खुली और पारदर्शी पहुँच।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण:** भारत में ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देना (Zero Import लक्ष्य)।
- **आईटी फॉर जॉब्स:** युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- **अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम:** बायोमेट्रिक अटेंडेंस और वाई-फाई जैसे त्वरित लाभ वाले प्रोजेक्ट्स लागू करना।

### आदिवासी क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति:

- **डिजिटल बुनियादी ढांचा (Infrastructure):** वर्तमान में '4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट' के माध्यम से वनांचलों में तेजी से मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, फिर भी कबीरधाम के बोडला जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में 'शैडो ज़ोन' (नेटवर्क विहीन क्षेत्र) एक बड़ी समस्या है। बिजली की अनियमित आपूर्ति और इंटरनेट की धीमी गति आज भी डिजिटल सेवाओं के निरंतर उपयोग में बाधा बनी हुई है।
- **वित्तीय एवं प्रशासनिक समावेशन:** प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) के कारण आदिवासियों को पेंशन और छात्रवृत्ति के लिए बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ते; अब वे स्थानीय 'कॉमन सर्विस सेंटर' (CSC) से ही लेन-देन कर रहे हैं। इससे बिचौलियों का हस्तक्षेप कम हुआ है और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता आई है।
- **सामाजिक और शैक्षिक बदलाव:** आदिवासी युवाओं में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया (यूट्यूब, व्हाट्सएप) का उपयोग बढ़ा है, जिससे वे अपनी स्थानीय कला और संस्कृति को वैश्विक पहचान दे रहे हैं। हालांकि आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि तकनीकी कौशल का अभाव भी है। यद्यपि 'पीएमजीदिशा' (PMGDISHA) जैसी योजनाओं ने लाखों आदिवासियों को कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान दिया है, परंतु उसका व्यावहारिक प्रयोग अभी भी सीमित है। विशेष रूप से कबीरधाम के बोडला जैसे क्षेत्रों में, जहाँ की बैगा जनजाति की अपनी विशिष्ट भाषा और संस्कृति है, वहाँ हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध डिजिटल इंटरफेस एक बड़ी रुकावट पैदा करता है। अधिकांश आदिवासी उपयोगकर्ता स्मार्टफोन का प्रयोग केवल

मनोरंजन तक ही सीमित रखते हैं; वे ऑनलाइन बैंकिंग, ई-लर्निंग या सरकारी पोर्टल्स का लाभ उठाने में हिचकिचाते हैं। तकनीकी ज्ञान की इसी कमी के कारण वे अक्सर 'साइबर ठगी' का शिकार भी होते हैं, जो उनमें डिजिटल सेवाओं के प्रति असुरक्षा की भावना पैदा करता है। डिजिटल साक्षरता और स्थानीय भाषाओं में सामग्री की कमी के कारण अभी भी एक बड़ा वर्ग तकनीकी लाभों से पूरी तरह नहीं जुड़ पाया है।

### सहभागिता का विश्लेषण:

आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया की सहभागिता धीरे-धीरे बढ़ रही है। मोबाइल फोन और इंटरनेट पैकेजों ने लोगों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल इंडिया वर्तमान में रीड की हड्डी बन गया है। इसके बिना पूरी ई-सेवा अनुपयोगी रहेगा।

ग्रामीण आदिवासी युवाओं में डिजिटल सेवाओं जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, UPI भुगतान, सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है। हालांकि, वृद्ध जनसंख्या और कम शिक्षित वर्ग अभी भी डिजिटल तकनीक से दूर है। सरकारी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुँच बढ़ाने में मदद की है।

### डिजिटल इंडिया का प्रभाव:

1- स्वास्थ्य पर प्रभाव: आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को डॉक्टरों से चिकित्सा सलाह मिल रही है, जिससे समय और यात्रा की बचत हो रही है। साथ ही, इंटरनेट के जरिए विभिन्न बीमारियों, उपचार और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी आसानी से उपलब्ध हो रही है। इसके बावजूद कई समस्याएँ बनी हुई हैं, जैसे अस्पतालों की भौगोलिक दूरी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता का अभाव, जिसके कारण इन सेवाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

2- रोजगार पर प्रभाव: डिजिटल इंडिया के तहत आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा अब डेटा एंट्री, ऑनलाइन सेवाओं और छोटे डिजिटल व्यवसायों में काम कर पा रहे हैं। साथ ही, विभिन्न सरकारी योजनाओं और रोजगार अवसरों की जानकारी भी अब ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है, जिससे लोगों की भागीदारी बढ़ी है। लेकिन डिजिटल कौशल की कमी, प्रशिक्षण की अनुपलब्धता और तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण कई लोग इन अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

3- आर्थिक प्रभाव: आर्थिक क्षेत्र में भी डिजिटल इंडिया का सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। UPI और मोबाइल बैंकिंग जैसे डिजिटल भुगतान माध्यमों से लेन-देन आसान, तेज और सुरक्षित हुआ है, जिससे नकदी पर निर्भरता कम हुई है। इसके अलावा, डिजिटल प्रक्रियाओं के कारण पारदर्शिता भी बढ़ी है और भ्रष्टाचार में कमी आई है। लेकिन अभी भी कई आदिवासी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की जानकारी का अभाव, डिजिटल साक्षरता की कमी और तकनीकी संसाधनों की सीमित उपलब्धता जैसी समस्याएँ मौजूद हैं, जो आर्थिक विकास में बाधा बनती हैं।

**चुनौतियाँ :**

आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया के क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं—

- कमजोर इंटरनेट और नेटवर्क सुविधा ।
- डिजिटल साक्षरता की कमी ।
- आर्थिक गरीबी और उपकरणों की कमी ।
- भाषा की समस्या (स्थानीय भाषा समर्थन की कमी) ।
- भौगोलिक दुर्गमता (पहाड़ी/वन क्षेत्र) ।
- तकनीकी प्रशिक्षण की कमी ।
- स्कूलों में डिजिटल संसाधन/तकनीकी की कमी ।

**निष्कर्ष:**

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बोड़ला ब्लॉक जैसे दुर्गम क्षेत्रों में 'डिजिटल इंडिया' अभियान न केवल एक तकनीकी क्रांति है, बल्कि यह आदिवासी समुदाय के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण का एक सशक्त आधार भी बन गया है। डिजिटल माध्यमों ने इस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक सीधी पहुँच आसान की है, जिससे बिचौलियों के हस्तक्षेप में कमी आई है और शासन में पारदर्शिता बढ़ी है। यद्यपि पहाड़ी भौगोलिक बनावट के कारण नेटवर्क की अनिश्चितता और डिजिटल साक्षरता की कमी आज भी मुख्य चुनौतियाँ बनी हुई हैं, फिर भी आदिवासी युवाओं की इस तकनीक में बढ़ती रुचि एक सकारात्मक भविष्य की ओर संकेत करती है। अंततः यदि बोड़ला के क्षेत्रों में तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ स्थानीय बोलियों में डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई जाए, तो यह अभियान आदिवासी समाज की पारंपरिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए उन्हें आधुनिक दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में सक्षम बनाएगा।

**संदर्भ सूची :**

1. स्टिबिट्ज़, जी. आर. (1942). 'डिजिटल बनाम एनालॉग कंप्यूटिंग'. बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज आर्काइव्स
2. Stibitz, G. R. (1942). "Digital vs Analog Computing". Bell Telephone Laboratories Archives. (संदर्भित: रैंडेल, बी., द ओरिजिन्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, 1973)।
3. भारत सरकार (2011). जनगणना 2011: अनुसूचित जनजाति सांख्यिकी रिपोर्ट. रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली।
4. तबस्सुम, एस.एस.जेड (2014) डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस अंगग आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज स्टूडेंट इन तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट ए स्टडी । इंटरनेशनल जर्नल आफ मेनेजिरियल स्टडीज एंड रिसर्च, वॉल्यूम-2, इश्यू-4
5. राव, पी., एवं अन्य (2021). भारत के आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन । जर्नल ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, 12(3), 45-62.

6. कौर, ए., एवं मोन्गा, एस. (2021)। व्यावसायिक युग में डिजिटल परिवर्तन।
7. शर्मा, ए. एवं बघेल, आर. (2022). छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातियों में डिजिटल साक्षरता की चुनौतियाँ: बोड़ला ब्लॉक का एक केस स्टडी। ग्रामीण विकास और तकनीक जर्नल, खंड 8(1)।
8. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) (2023). डिजिटल इंडिया वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2022–23. भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, कबीरधाम (2024). जिला सांख्यिकी पुस्तिका: कबीरधाम जिला (छत्तीसगढ़). आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन।
10. जनजातीय कार्य मंत्रालय (2024). वार्षिक रिपोर्ट 2023–24: जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और विकास. भारत सरकार।
11. यादव, आर. के. (2024). छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया: चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ . जर्नल ऑफ रूरल एंड ट्राइबल स्टडीज, 18(1), 78–95.
12. अली, एल. (2025). ग्रामीण और जनजातीय भारत में डिजिटल इंडिया का प्रभाव: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। भारतीय सामाजिक अनुसंधान पत्रिका, खंड 12(2), पृ. 45–60।
13. यादव, एस. के. (2024). 'डिजिटल इंडिया और आदिवासी सशक्तिकरण संभावनाएँ और बाधाएँ'।
14. सिंह, कुलदीप, कुमार, संजीव एवं तालुकदार, मोहम्मद, (2024)। डिजिटल परिवर्तन और भारत में पर्यटन व्यवसाय पर इसका प्रभाव।
15. पी.आई.बी. (PIB) (2025). आदिवासी क्षेत्रों में 4G संचुरेशन योजना की प्रगति. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
16. कुमार, एम., एवं सिंह, वी. पी. (2025). डिजिटल इंडिया 2.0 और आदिवासी समुदायों का समावेशन: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बोड़ला ब्लॉक का एक तुलनात्मक विश्लेषण। जर्नल ऑफ एडवांस्ड रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, 22(1), 15–32
17. भारतनेट पोर्टल (2026). ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की स्थिति (छत्तीसगढ़). <https://bbl.nic.in>